बकाया भुगतान को चीनी का दाम बढ़ाने की मांग

चीनी मिल संगठन ने सरकार को पत्र लिखकर एमएसपी बढ़ाने की अपील की

नई दिल्ली। देश के गन्ना किसानों के हजारों करोड़ रुपये बकाए का भुगतान करने के लिए मिलों ने सरकार से चीनी का दाम बढ़ाने की मांग की है। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि चीनी मिलों ने सरकार से बकाया भुगतान में मदद के लिए अपना मुनाफा बढ़ाने की बात कही है।

अधिकारी के अनुसार, भारतीय चीनी मिल संगठन (ईस्मा) ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने जाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि मिल गेट पर अभी चीनी का एमएसपी 29 रुपये प्रति किलोग्राम है जिसे बढ़ाकर 35-36 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाना चाहिए। तभी चीनी मिलों के पास गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए अतिरिक्त पूंजी आ सकेगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ईस्मा के आंकड़ों के अनुसार एक साल पहले के मुकाबले 31 दिसंबर, 2018 तक देश का चीनी भंडार दोगुना बढ़कर 1.54 करोड़ टन हो गया है। एजेंसी

19.20 हजार करोड़ बकाया है चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का

29 रुपये है अभी मिल गेट पर चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य

निर्यात घटाने की मंशा : संगठन का कहना है कि चीनी का एमएसपी बढ़ाने से मिलें घरेलू बाजार में इसकी बिक्री में इजाफा करने की ओर प्रेरित होंगी जिससे निर्यात घटाने और वैश्विक कीमतों में भी मदद मिलेगी। गन्ना किसानों की ओर से बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान किए जाने की मांग से चीनी मिलें दबाव में हैं, जिसके लिए किसान लगातार विरोध-प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 2018-19 में देश का कुल चीनी 35 लाख टन हो रहा जो सरकार के तय लक्ष्य 50 लाख टन से काफी पीछे है।

दोगुना हो जाएगा बकाया

पिछले साल 31 दिसंबर तक गन्ना किसानों का कुल बकाया करीब 19 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया था। संगठन का कहना है कि अगर चीनी मिलों के पास जरूरी इजाफा नहीं बढ़ा तो बकाया राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ हो सकती है। संगठन ने पत्र में लिखा कि अभी मिलों को उत्पादन लागत सरकार द्वारा तय बिक्री मूल्य से ज्यादा है। ऐसे में चीनी की एमएसपी बढ़ाने से मिलों को तीन माह में 20 हजार करोड़ मिल सकते हैं।